

✓ N

बिजनौर केसरी

चीनी मिलों में मरम्मत कार्य बन्द होने से...

प्रांतीय सम्मेलन की सफलता को लेकर बनाई रणनीति

धामपुर, (सुशील अग्रवाल): उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्र संघ बिजनौर की धामपुर-नगीना मार्ग स्थित के.एम.ईटर कालेज में जिलाध्यक्ष मुकेश सिन्हा की अध्यक्षता में तथा जिला मंत्री अंशुल कुमार के संचालन में सम्पन्न हुई बैठक में आगामी 19 अक्टूबर को अलीगढ़ में होने वाले संगठन के प्रांतीय सम्मेलन को सफल बनाने रणनीति बनाई गई तथा संगठन की मजबूती पर बल प्रदान किया गया। बैठक में चेतनारायण गुट के कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल कुमार ने संगठन की मांगों का समर्थन किया। बैठक को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसी भी संगठन की मजबूती उससे जुड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एकता से होती है और यदि हममें बिखराव होगा तो हमें कोई भी तोड़ सकता है। वक्ताओं ने कहा कि जब तक हम एक हैं तब तक हमारा कोई उत्पीड़न नहीं कर सकता है, इसलिए हमें एक-दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्र संघ का एक प्रांतीय सम्मेलन आगामी 19 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां जोरशोर से जारी हैं।

किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें

गन्ने के मूल्य के निर्धारण का हल न निकलने की स्थिति में उ.प्र. शुगर मिल एसोसिएशन ने लिया निर्णय

धामपुर, (सुशील अग्रवाल): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेरार्ड सत्र से पूर्व गन्ने के दामों को मनमाने ढंग से घोषित करने से प्रदेशभर की निजी शुगर मिलों के सामने हर वर्ष उत्पन्न होने वाली वित्तीय घाटे की समस्या किसी से छुपी नहीं रही है और यह समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब गन्ने का मूल्य और चीनी के दामों के अनुपात में काफी अंतर होता है। पेरार्ड सत्र 2013-14 के समाप्त होने तक चीनी के दामों में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई। जिस कारण धामपुर शुगर मिल सहित प्रदेशभर की 95 निजी मिलों के सामने 260 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से गन्ना मूल्य भुगतान करने की समस्या खड़ी हो गई और इस तरह से पेरार्ड सत्र खत्म होते-होते बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की रकम 7 हजार करोड़ तक पहुंच गई। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कुल 119 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 95 निजी चीनी मिल हैं और

गन्ना एवं चीनी मूल्य के बीच कोई सर्वमान्य हल न निकलने के कारण उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन ने गत 14 अगस्त से सम्मत निजी मिलों में पेरार्ड सत्र 2014-15 की तैयारियों हेतु मरम्मत का कार्य पूर्णरूप से बन्द किया हुआ है। मरम्मत कार्य अभी तक शुरू न होने से इस वर्ष शुगर मिलों का समय से चलना लगभग असंभव नजर आ रहा है। गन्ने की फसल के खेतों में खड़ा रहने के कारण किसानों के सामने गेहूं की बुवाई को लेकर संकट बना हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह पेरार्ड सत्र 2014-15 से पूर्व चीनी के दामों को दृष्टिगत रखते हुए गन्ने के मूल्य का निर्धारण कर दें। वरना इस वर्ष गन्ने की दुर्गति को होने से कोई नहीं रोक सकता है। उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन के सचिव दीपक गुप्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास प्रमुख सचिव को गत 27 सितम्बर 2014 को पत्र प्रेषित कर



अवगत कराया था कि गत 10 जनवरी 2014 को कृषि उत्पादन आयुक्त उ.प्र. की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। जिसका काम गत पेरार्ड सत्र में खरीदे गए गन्ने पर 8.97 रुपये प्रति कुंठ की वित्तीय सहायता देने हेतु गन्ना मूल्य एवं चीनी मिल के दामों के अनुपात

के अनुसार निर्धारित करवाना था और इस कमेटी को चीनी मिलों की सुनवाई करके तीन माह के भीतर यानि 10 अप्रैल 2014 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। पत्र में यह भी अवगत कराया गया है कि चीनी मिल एसोसिएशन की सदस्य निजी चीनी मिलें पेरार्ड सत्र प्रारम्भ करने के लिए सहमत नहीं थे। इस सम्बंध में चीनी मिल एसोसिएशन द्वारा समय-समय पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा इस व्यक्तिगत रूप से चीनी उद्योग की संकटपूर्ण वित्तीय स्थिति से भी अवगत कराया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गत 20 नवम्बर 2013 को 280 रुपये प्रति कुंतल (एस.ए.पी.) गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया। चीनी मिलों द्वारा लगातार वित्तीय घाटे एवं चीनी के दामों के आधार पर कहा गया था कि चीनी मिले 225 रुपये प्रति कुंतल से अधिक गन्ना मूल्य भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मनमाने ढंग से गन्ने

का मूल्य तय किया, जो निजी चीनी मिलों के लिए परेशानी का सबब बना। यही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार सहकारी चीनी मिलों के कृषकों को लगभग 86 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। जबकि निजी चीनी मिलों के कृषकों को मात्र 8.97 रुपये प्रति कुंतल की वित्तीय सहायता दे रही है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय उस समय कारगर साबित होगा जब सरकार द्वारा दिये जाने वाले 8.97 रुपये प्रति कुंतल की वित्तीय सहायता का लाभ कृषकों को सीधे या उनसे सम्बंधित गन्ना समितियों को अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के सापेक्ष कर दिया जाए। प्राइवेट चीनी मिलों के सूत्रों का कहना है कि जब तक चीनी के बाजार मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए गन्ने के मूल्य के निर्धारण को लेकर कोई सर्वमान्य हल नहीं निकलता है तब तक वह चीनी मिलों को चलाने में पूरी तरह से असमर्थ है।